

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा योजना: नीतिगत सुधार एवं भावी रणनीतियाँ - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

कोहन लाल साहू¹ ; डॉ. विभा मिश्रा²

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.22880516>

Review: 31/06/2026

Acceptance: 09/07/2026

Publication: 31/07/2026

सारांश:

भारत के शिक्षा तंत्र में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जो समावेशिता, कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों पर आधारित है। इस नवीन नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने का सबसे सशक्त माध्यम 'समग्र शिक्षा योजना' है। प्रस्तुत शोध पत्र विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में यह विश्लेषण करता है कि नई शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा अभियान के बीच किस प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक बनावट और बड़ी जनजातीय जनसंख्या के कारण शैक्षिक प्रसार के मामले में कुछ अलग तरह की बाधाओं का सामना करता है। यह अध्ययन राज्य सरकार की उन अभिनव योजनाओं का गहराई से मूल्यांकन करता है, जिनमें 'स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय', 'अंगना म शिक्षा' कार्यक्रम, तथा आदिवासी बोलियों (जैसे हल्बी और गोंडी) में प्रारंभिक शिक्षा देने के प्रयास शामिल हैं। अंततः यह आलेख सरगुजा और बस्तर जैसे सुदूर वनांचलों में तकनीकी असमानता (डिजिटल डिवाइड) और शाला-त्याग (ड्रॉपआउट) की समस्याओं को इंगित करते हुए भविष्य की एक मजबूत और व्यावहारिक कार्ययोजना प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द (Keywords): नव शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान, छत्तीसगढ़ का शैक्षिक ढांचा, समावेशी अध्यापन, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (FLN), मातृभाषा आधारित शिक्षा।

1. पृष्ठभूमि (Background)

किसी भी देश की सामाजिक-आर्थिक उन्नति का मुख्य आधार उसकी शिक्षा प्रणाली होती है। करीब साढ़े तीन दशकों के लंबे अंतराल के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का मूल ध्येय एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था का निर्माण करना है, जहाँ गुणवत्ता और समानता दोनों का समावेश हो। इस नीतिगत विजन को यथार्थ का रूप देने के लिए 'समग्र शिक्षा योजना' को पुनर्गठित किया गया है। यह योजना अब पूर्व-

¹शोधार्थी (शिक्षा), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), इंडिया

²शोध निदेशक, प्राचार्य, डी.पी. विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), इंडिया

प्राथमिक (प्री-स्कूल) से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को अलग-अलग टुकड़ों में न देखकर एक अखंड प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करती है।

सन् 2000 में अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य की कुल आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा जनजातीय समुदायों का है। यहाँ के घने वन क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ियाँ और कुछ हिस्सों में व्याप्त वामपंथी उग्रवाद शिक्षा की पहुँच में निरंतर बाधक रहे हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बीच, NEP 2020 के आलोक में समग्र शिक्षा योजना को प्रदेश में लागू करना महज एक सरकारी औपचारिकता नहीं, अपितु एक गहरी सामाजिक और आर्थिक जरूरत है।

2. शोध का लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives of Research)

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख दिशा-निर्देशों और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्संबंधों की विस्तृत विवेचना करना।
2. समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश में किए गए नवीन नीतिगत बदलावों की समीक्षा करना।
3. शिक्षा के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नवाचारी पहलों के वास्तविक प्रभाव का आकलन करना।
4. भौगोलिक तथा जनसांख्यिकीय (Demographic) चुनौतियों को चिन्हित कर उनके समाधान हेतु भावी रणनीतियों का प्रस्ताव रखना।

3. शोध का महत्व (Importance of Research)

यह शोध आलेख इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ जैसे बहुसांस्कृतिक और आदिवासी बहुल सूबे में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। यह अध्ययन जहाँ एक ओर मातृभाषा में शिक्षण जैसी सफल नीतियों की सराहना करता है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी संसाधनों की कमी और तकनीकी विभाजन (Digital Divide) जैसी गंभीर समस्याओं की ओर नीति-नियंताओं का ध्यान आकृष्ट कराता है। इस शोध के निष्कर्ष भविष्य में शैक्षिक विकास की दिशा तय करने में प्रासंगिक साबित होंगे।

4. NEP 2020 और समग्र शिक्षा का एकीकरण

नई शिक्षा नीति ने पुरानी 10+2 व्यवस्था को विस्थापित करते हुए 5+3+3+4 के अभिनव ढाँचे को अपनाया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने पहली बार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) को औपचारिक स्कूली तंत्र के भीतर समाहित किया है।

समग्र शिक्षा 2.0 का स्वरूप: NEP 2020 की नवीन अनुशंसाओं के आधार पर समग्र शिक्षा अभियान को अपग्रेड किया गया है। यह अब राज्य सरकारों को दीक्षा (DIKSHA), निष्ठा (NISHTHA) और निपुण भारत (NIPUN Bharat) महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक ढांचागत और वित्तीय संबल प्रदान कर रहा है।

5. छत्तीसगढ़ में नीतिगत सुधार एवं प्रमुख पहलें

5.1 'अंगना म शिक्षा' - बुनियादी साक्षरता का अभिनव प्रयोग: NEP 2020 कक्षा 3 तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) सुनिश्चित करने पर बल देती है। इसे साकार करने हेतु छत्तीसगढ़ में 'अंगना म शिक्षा' नामक एक अनूठा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत माताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे घर के सहज वातावरण में खेल-खेल के माध्यम से अपने बच्चों को अक्षर एवं अंकों की पहचान करा सकें।

5.2 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परियोजना (SAGES): समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उत्कृष्ट शिक्षा पहुँचाने की मंशा से राज्य शासन ने 'स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिंदी माध्यम स्कूल' स्थापित किए हैं। यह पहल NEP 2020 के 'समानता और समावेशन' (Equity & Inclusion) सिद्धांत का मूर्त रूप है, जिसके माध्यम से साधारण परिवारों के बच्चों को सर्वसुविधायुक्त और आधुनिक शिक्षा सुलभ हो रही है।

5.3 स्थानीय बोलियों में शिक्षण कार्य: स्थानीय भाषा में अध्यापन को NEP 2020 ने विशेष महत्व दिया है। छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी अंचलों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने हल्बी, गोंडी, भतरी आदि बोलियों में द्विभाषी किताबें निर्मित की हैं। अपनी ही भाषा में शिक्षा मिलने से आदिवासी बच्चों का स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ा है और शाला-त्याग (Dropout) की दर में आशातीत कमी दर्ज की गई है।

6. क्रियान्वयन के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ

- **दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ:** राज्य के नक्सल प्रभावित और अति-दुर्गम इलाकों में सुरक्षित एवं स्थायी विद्यालय भवनों का निर्माण आज भी एक विकट समस्या है।
- **तकनीकी असमानता (Digital Divide):** ग्रामीण और वन क्षेत्रों में निर्बाध इंटरनेट सेवा तथा स्मार्ट उपकरणों का अभाव ई-लर्निंग की राह में बड़ा रोड़ा है।
- **विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों का अभाव:** ग्रामीण स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों के योग्य शिक्षकों की भारी किल्लत है।

7. आगामी कार्ययोजना एवं महत्वपूर्ण सुझाव

- **क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का सशक्तिकरण:** एक बड़े विद्यालय को केंद्र (नोडल) मानकर आसपास की छोटी शालाओं के मध्य शिक्षकों, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- **स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा:** कृषि, वनोपज प्रसंस्करण और पारंपरिक हस्तकला (जैसे डोकरा आर्ट) को स्कूली व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।
- **शिक्षकों हेतु विशेष प्रोत्साहन:** दुर्गम और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सेवा देने वाले शिक्षकों को सुरक्षित आवास और अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- **वैकल्पिक शिक्षण मॉडल (Off-grid Solutions):** जिन इलाकों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन और प्री-लोडेड एसडी कार्ड के जरिये शैक्षणिक सामग्री पहुँचाई जाए।

8. निष्कर्ष (Conclusion):

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निश्चित रूप से एक भविष्योन्मुखी दस्तावेज है, जिसे धरातल पर समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से ही उतारा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में, मातृभाषा आधारित शिक्षा और 'अंगना म शिक्षा' जैसी योजनाएं अत्यंत सराहनीय कदम हैं। यदि राज्य सरकार भौगोलिक बाधाओं और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों को पार करने के लिए सुझाई गई रणनीतियों पर गंभीरता से अमल करती है, तो छत्तीसगढ़ संपूर्ण देश के समक्ष समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक अनुकरणीय प्रतिमान स्थापित कर सकेगा।

9. संदर्भ सूची (References)

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP):** शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मूल नीति दस्तावेज।
- **समग्र शिक्षा 2.0 रूपरेखा:** स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन क्रियान्वयन दिशानिर्देश।
- **विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन (2022-23):** स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित प्रामाणिक आंकड़े।
- **निपुण भारत मिशन (NIPUN Bharat):** मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय मिशन के दिशा-निर्देश।
- **SCERT छत्तीसगढ़ के दस्तावेज:** बहुभाषी शिक्षण प्रक्रिया तथा जनजातीय बोलियों (हल्बी, गोंडी इत्यादि) में पाठ्यक्रम विकास से संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट।
- **शासकीय अधिसूचनाएं:** 'स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना' तथा 'अंगना म शिक्षा' के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र।